SONTOSH MOHAN DEV): (a) Government has been giving financial assistance by way of plan and non-plan loans to Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL). HSCL on its own has also been making efforts to improve its performance by identifying jobs to be taken in the steel sector, reduction in establishment cost and improvement in efficiency of man power.

(b) The Voluntary Retirement Scheme (VRS) is a voluntary scheme, and the question of enforcing it does not arise. VRS has been in operation in HSCL since 1988 & as on 30th November, 1993, 4116 employees have opted for VRS. HSCL has also not written to Labour Departments of State Governments seeking approval for retrenchment of labour force.

Modernisation of Bokaro Steel Plant

1167. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL be pleased to state the companies shortlisted for taking the work of modernisation of Bokaro Steel Plant indicating the expenditure involved and targets set therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): Government have on 23-7-1993 approved the investment proposal of Steel Authority of India Limited to modernise Bokaro Steel Plant (Stage I) at an estimated capital cost of Rs. 1625.79 crores inclusive of foreign exchange component of Rs. 283.50 crores. The project will be implemented by July, 1997.

The companies so far short listed for the global packages as prime bidders are as follows:—

(i) M/s. Mannesman Demag Huttentechnik, Germany.

(ii) M/s. Voest Alpine, Austria.

(iii) M/s. Davy International, England.

(iv) M/s. SMS Schloemann Siemag, Germany.

(v) M/s. Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

(vi) M/s. Mannesmann Demag Sack, Germany.

(vii) M/s. United Engineering Inc., USA.

(viii) M/s. Mitsubishi Corporation, Japan.

Higher Growth Rate in Steel Consumption

1168. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the current decade is likely to witness a higher growth rate in steel consumption in developing countries than in developed countries;

(b) if so, whether the market potential has been assessed for steel exports to the developing countries; and

(c) what are the plans in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The large public sector steel producers like SAIL are aware of the likely increase in steel consumption in the developing countries and are keeping abreast with the latest trends in the international market for steel products. They have planed to maximise their export thrust to developing countries and newly industrialised countries like china, Burma, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Nepal, Bangladesh, etc.

Diatari Steel Project in Orissa

1169. SHRI H. HANUMANTHAPPA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of STEEL be pleased to state the stage at which the proposed Daitari Steel Project in Orissa stands?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): The foreign investment proposal for setting up a steel plant near

Daitari in Orissa under the name of "Kalinga Steels (India) Limited" has earlier been cleared by Government of India. This plant is being set up in pursuance of a Memorandum of Understanding signed between Government of Orissa and Dr. Swraj Paul of the Caparo Group Limited. Government of Orissa have informed that Detailed Project Report is expected sometime by July 1994. They have also informed that 4000 acres of land has already been acquired.

कमजोर वर्गों के लिये आवास

1176. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये गैर सरकारी क्षेत्र के माध्यम से मकानों का निर्माण करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के लिये कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) क्या "सन् 2000 तक सभी के लिये आवास" नामक जैसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) इन चार महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, मध्यम और निम्न आय वर्गों के लोगों के लिये सरकारी सहायता से कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और क्या इन वर्गों के लोगों को उचित रियायती दरों पर मकान दिये जाते हैं और इस संबंध में लघुतम सीमा कितनी है; और

(ङ) आम जनता को आसान किस्तों पर मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक रिहायसी एकक के लिये किस्त की सीमा कितनी निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय आवास नीति में सहकारी और अन्य समुदाय आधारित संगठनों तथा निजी विकासकों को, लाभ-ग्रहियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न आश्रय सम्बन्धी कार्यकलापों शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार किया गया है। आवास मूल रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व होने के नाते वे अपने आवास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र को शामिल करने की पद्धति और सीमा का निर्णय करने में स्वतन्त्र हैं।

(ग) राष्ट्रीय आवास नीति का एक मुख्य लक्ष्य आगामी 10 वर्षों में गृह-विहीनता को कम करना है। राज्य सरकारों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं और कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गयी है।

(घ) एल आई जी/एम आई जी आवास के लिए केन्द्र सरकार की कोई सहायता सीधे नहीं दी जाती है। तथापि, एल आई जी और एम आई जी श्रेणियों के लिए आवास स्कीमें प्रारम्भ करने हेतु राज्य एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से संस्थागत वित्त उपलब्ध है। हुडको ऋण की सहायता से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में गत तीन वर्षों अर्थात् 1990–91 से 92–93 के दौरान बनाए गए एल आई जी और एम आई जी के मकानों का विवरण इस प्रकार है :–

शहर	1990–91		1991–92		1992–93	
	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी	एलआईजी	एमआईजी
कलकत्ता	140	172	112	592	—	160
बम्बई	1108	1910	1420	—	1142	472
मद्रास	3161	496	624	—	1024	198